Yogoda Satsanga Mahavidyalaya

M. Com Semester - II

Subject: Business Environment (CCCOM 201)

Topic: **आर्थिक नीति: एक सिंहावलोकन 1991 के बाद से सरकारी नीतियों में बदलाव।**

Ravindra Kumar, Associate Professor Department of Commerce

आर्थिक नीति: एक सिंहावलोकन 1991 के बाद से सरकारी नीतियों में बदलाव।

1991 के बाद से, भारत की आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ये बदलाव 1990 के दशक की शुरुआत के आर्थिक संकट को दूर करने और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से एकीकृत करने के लिए शुरू किए गए थे। यहां प्रमुख परिवर्तनों का अवलोकन दिया गया है:

1. आर्थिक उदारीकरण (1991 से आगे)

• नई औद्योगिक नीति (1991): सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कम कर दी गई, औद्योगिक लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया (कुछ क्षेत्रों को छोड़कर), और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया।

• वित्तीय क्षेत्र में सुधार: वैधानिक तरलता और नकदी आरक्षित आवश्यकताओं को कम करके, निजी और विदेशी बैंकों को संचालन की अनुमति देकर और सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड) जैसे नियामक निकायों की स्थापना करके बैंकिंग प्रणाली को मजबूत किया गया।

• व्यापार नीति सुधार: टैरिफ और आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और निर्यात-उन्मुख विकास को बढ़ावा देना।

2. निजीकरण एवं विनिवेश

• सार्वजनिक क्षेत्र सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में हिस्सेदारी बेचकर निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। दूरसंचार, विमानन और ऊर्जा जैसे उद्योगों में महत्वपूर्ण विनिवेश हुआ।

• विनिवेश नीति: प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए विनिवेश विभाग (अब निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) की स्थापना की गई।

3. कर सुधार

• 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का परिचय: अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत किया गया, कई राज्य और केंद्रीय करों को एक कर व्यवस्था से बदल दिया गया, अनुपालन को सरल बनाया गया और कर राजस्व में वृद्धि हुई।

• प्रत्यक्ष कर संहिता और कॉर्पोरेट कर सुधार: निवेश को आकर्षित करने के लिए कर कानूनों को सरल बनाया गया और कॉर्पोरेट कर दरों को कम किया गया।

4. बैंकिंग और वित्तीय समावेशन

• बैंकिंग सुधार: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एकीकरण, नए बैंकिंग लाइसेंस की शुरूआत और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना।

• वित्तीय समावेशन: सभी नागरिकों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) जैसी योजनाएं शुरू की गईं।

5. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सुधार

• उदारीकृत एफडीआई नीति: खुदरा, रक्षा, बीमा और रियल एस्टेट जैसे क्षेत्रों में उच्च विदेशी स्वामित्व की अनुमति। निवेश प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों के लिए स्वचालित मार्गों की शुरूआत।

6. बुनियादी ढांचे का विकास

• सड़कें और राजमार्ग: सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज और भारतमाला परियोजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए।

• शहरी बुनियादी ढांचा: शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन और AMRUT (कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन) जैसी पहल शुरू की गई।

7. श्रम सुधार

• श्रम संहिता: अनुपालन को सरल बनाने और श्रम बाजार के लचीलेपन को बढ़ाने के लिए 44 श्रम कानूनों को 4 संहिताओं (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा) में समेकित किया गया।

8. कृषि सुधार

• आधुनिकीकरण की पहल: मशीनीकरण को बढ़ावा दिया गया, सिंचाई में सुधार किया गया और किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता के लिए पीएम-किसान जैसी योजनाएं शुरू की गईं।

• बाजार सुधार: कृषि उपज के लिए एक राष्ट्रीय बाजार बनाने और किसानों को सीधे खरीदारों को बेचने की अनुमति देने के लिए कानून बनाए गए, हालांकि बाद में कुछ सुधारों को निरस्त कर दिया गया।

9. प्रौद्योगिकी और नवाचार

• डिजिटल इंडिया पहल: इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है।

• स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया: स्टार्टअप और उद्योगों के लिए प्रोत्साहन और समर्थन के माध्यम से उद्यमिता और विनिर्माण को प्रोत्साहित किया गया।

10. सामाजिक क्षेत्र सुधार

• स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा: स्वास्थ्य बीमा के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं और साक्षरता और कौशल विकास में सुधार के लिए विभिन्न शिक्षा पहल शुरू की गईं।

• सामाजिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा उपायों जैसी पेंशन योजनाएं शुरू कीं।

प्रभाव और चुनौतियाँ

इन सुधारों से मजबूत आर्थिक विकास हुआ है, विदेशी निवेश बढ़ा है और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है। हालाँकि, चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें आय असमानता को संबोधित करना, रोजगार सृजन सुनिश्चित करना, पर्यावरणीय स्थिरता का प्रबंधन करना और नियामक बाधाओं से निपटना शामिल है।

कुल मिलाकर, 1991 के बाद के आर्थिक नीति परिवर्तनों ने भारत की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया है, जिससे यह वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गया है।